भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1136

उत्तर देने की तारीख-10/02/2025

ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता दर बढ़ाने की पहल

†1136. **डॉ. गुम्मा तनुजा रानी:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में वर्तमान साक्षरता दर का राज्यवार ब्यौरा क्या हैं;
(ख) सरकार द्वारा इन क्षेत्रों में विशेषकर महिलाओं और अन्य कमजोर समुदायों की साक्षरता दर में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;
(ग) क्या विगत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा इस संबंध में कोई विशिष्ट पहल की गई है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क): सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के अनुसार देश के ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता दर का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुलग्नक** में है।

(ख) से (घ): देश में वयस्कों के बीच ग्रामीण साक्षरता दर सहित साक्षरता दर में सुधार करने के लिए भारत सरकार ने दिनांक 1 अप्रैल, 2022 से 2027 तक नव भारत साक्षरता कार्यक्रम (एनआईएलपी) नामक एक केंद्र प्रायोजित योजना शुरू की है, जिसे उल्लास: समाज में सभी के लिए आजीवन शिक्षा की समझ के रूप में जाना जाता है। एनईपी 2020 के अनुरूप यह योजना उन वयस्कों (15 वर्ष और उससे अधिक आयु के) जो स्कूल नहीं जा पाते, को लक्षित करती है। इस योजना के पाँच घटक हैं: (i) आधारभूत साक्षरता और संख्याज्ञान, (ii) महत्वपूर्ण जीवन कौशल, (iii) मूलभूत शिक्षा, (iv) व्यावसायिक कौशल और (v) सतत शिक्षा।

यह योजना हाइब्रिड मोड में कार्यान्वित की जा रही है, जिससे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को महत्वपूर्ण जीवन कौशल, डिजिटल और वित्तीय साक्षरता सहित आधारभूत साक्षरता और संख्याज्ञान प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड अपनाने की सुविधा मिलती है। उल्लास पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने के लिए स्वैच्छिकता के माध्यम से स्कूल मंचों और सामुदायिक जुड़ाव का उपयोग करते हुए भारत को 'जन-जन साक्षर' जो कर्तव्यबोध (कर्तव्य की भावना) से प्रेरित है, बनाने की दृष्टि से काम करता है। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों, शैक्षिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों, महिलाओं और अन्य कमजोर समुदायों आदि पर केंद्रित है।

शिक्षार्थियों और स्वयंसेवी शिक्षकों को पंजीकृत करने के लिए एक समर्पित उल्लास मोबाइल ऐप विकसित किया गया है और यह 26 भाषाओं में प्राइमर तक पहुँच प्रदान करके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को भी सक्षम बनाता है। निरंतर प्रयासों से, उल्लास के तहत 2 करोड़ से अधिक शिक्षार्थियों को पंजीकृत किया गया है और 1 करोड़ से अधिक शिक्षार्थी पहले ही देश भर में मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान आकलन परीक्षा (एफएलएनएटी) नामक साक्षरता परीक्षा में शामिल हो चुके हैं।

****

<u>अनुलग्नक</u>

माननीय संसद सदस्या डॉ. गुम्मा तनुजा रानी द्वारा 'ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता दर बढ़ाने की पहल' के संबंध में दिनांक 10.02.2025 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1136 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

भारत की राज्यवार ग्रामीण साक्षरता दर

क्र.सं.	राज्य\संघ राज्य क्षेत्र	2023-24
	अखिल भारतीय	**77.5**
1	आंध्र प्रदेश	67.5
2	अरुणाचल प्रदेश	82.9
3	असम	86.2
4	बिहार	73.3
5	छत्तीसगढ़	76.6
6	दिल्ली	84.8
7	गोवा	92.8
8	गुजरात	79.6
9	हरियाणा	81.3
10	हिमाचल प्रदेश	88.1
11	झारखंड	74.3
12	कर्नाटक	78.1
13	केरल	94.2
14	मध्य प्रदेश	71.6
15	महाराष्ट्र	83.2
16	मणिपुर	90.9
17	मेघालय	93.6
18	मिजोरम	98.1
19	नागालैंड	95
20	ओडिशा	76.9
21	पंजाब	81.1
22	राजस्थान	72.5
23	सिक्किम	82.2
24	तमिलनाडु	81.2
25	तेलंगाना	69.9
26	त्रिपुरा	92.8
27	उत्तराखंड	82.2
28	उत्तर प्रदेश	76.5
29	पश्चिम बंगाल	80.3
30	अंडमान और निकोबार द्वीप	90.6
31	चंडीगढ़	*
32	दादरा एवं नगर हवेली	75.8
33	दमन और दीव	
34	जम्मू एवं कश्मीर	81.4
35	लद्दाख	79.8
36	लक्षद्वीप	99.5
37	पुदुचेरी	90.2

*वर्ष 2023-24 के लिए सर्वेक्षण हेतु चंडीगढ़ के सम्पूर्ण क्षेत्र को शहरी माना गया है।

आंकड़ों का स्रोत - आवधिक श्रम बाल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

*****